





भारतीय बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष: जश्न में भी बनाए रखें होश

भारतीय राष्ट्रीय जीव, 'बाघ', वन्यजीव भर नहीं है, यह जिंदगी की बुनियाद, उसके आधार जल, वायु समेत समस्त जलवायु का संरक्षक भी है। एक बड़े जंगली पर्यावास की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठकर बाघ क्रियाशील परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, आग्धिर में जो हम सबको जीवनदायी जल एवं वायु प्रदान करने में मददगार होता है। भारतीय बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर है। अब इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन पांच दशकों में प्रोजेक्ट टाइगर ने कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं। बाघ पाए जाने वाले 20 राज्यों में इसकी मौजूदगी कमोवेश सफलता रूपी संतोष तो देता है। फिर भी, अभी बहुत सारे कारगर उपायों पर विचार करना आवश्यक है। भारत पर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में बाघों को बचाने के प्रयास में भारत शीर्ष पर है। विश्व भर के बाघों की 70% आबादी भारत में है। तभी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। प्रोजेक्ट टाइगर की

ताइगर रिजर्व  
का समूल  
वायांच एजेंसी ने  
तकरीबन 75,000 वर्ग किलोमीटर  
हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50  
रहे हैं और सूत्रों से, नई गण  
आंकड़े को बताते हैं।  
प्रधानमंत्री इस 3  
का सिक्का भी जारी  
संदर्भ में 2018  
गौर करना समर्पित  
रिपोर्ट बताती है।  
लगभग टाइगर रिजर्व  
मौजूदा बायांच व  
अधिक रखने की  
टाइगर रिजर्व व  
घनत्व प्रति  
किलोमीटर में एक  
है। चार-पांच टाइगर  
तो संख्या नगण्य  
कुछ बाघ वैज्ञानिकों  
है कि यदि सारे

पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर  
तो बाघों की संख्या 5,000 तक  
है। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक  
संपूर्ण भारतीय बाघ पर्यावास की

रत में फैला  
साल पूरे हो  
। 2022 के  
जाएगा एवं  
प्रसर पर 50  
करेंगे । इस  
रिपोर्ट पर  
वीन होगा ।  
एक आधी के  
वर्ष की क्षमता  
संख्या से  
15- 20व  
बाधों का  
100 वर्ग  
से भी कम  
प्ररिज्ञ में  
है । जबकि  
का मानना  
इगर रिज्ञ  
क्याशील हो  
पहुंच सकती  
कहा है कि  
की क्षमता

10,000 से 12,000 बाधों को  
सकती है । हमें वैज्ञानिक तर  
पर्यावासों के प्रबंधन में  
इकोलॉजिकल सम्पद्धि की आव  
डॉ रघु चुंडावत, डॉक्टर उल्लास  
वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक  
कोशिश एवं जसवीर सिंह चौहान  
कुमार, डॉ पावला, श्रीनिवास  
अधिकारियों का अनुभव राष्ट्रीय  
प्राधिकरण के साथ मिलकर प्रो  
को सम्पद्ध कर सकने में स  
समीपवर्ती समुदायों का योगद  
करना आवश्यक है । बढ़ती इंसान  
घटते वन क्षेत्र, सिकुद्दती नदियां  
स्रोत, बाघ संरक्षण में एक बड़ी  
हम विकसित होने की लडाई में  
है । अनेक परियोजनाओं का का  
पर्यावासों के लिए एक बड़ी  
ईकोट्रूज़िम को भी पर्यावास व  
अनुसार देखना आवश्यक होगा ।

हाल में ही बाधों के बढ़ा  
मानव- वन्यजीव द्वंद्व में वृद्धि  
भावनात्मक तरीके से देखने

बने की हो क से बाघ और भी यक्ता है। एवं कारंथ के महती डॉ सुहास रूपिंति सरीखे बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर सम होगा। यह सुनिश्चित ही आबादी, सूखते जल चुनौती है। यही पीछे नहीं न्वयन बाघ नौती है। क्षमता के संख्या से ई है। इसे के बजाय वैज्ञानिक सुझाव के आधार पर प्रबंधन को समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करना आवश्यक होगा। बाघ पर्यावासों को जीवनदायिनी जल का स्रोत एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले नील- हरित संरचना के रूप में प्रभावी रूप से देखना आवश्यक है। भारतीय बड़ी जनसंख्या को पीने का पानी एवं साँस देने के लिए हवा, दोनों ही जैव विविधता आधारित है क्योंकि बाघ पानी पिलाता है! बाघ खेती करता है! एवं बाघ स्कूल भी लगाता है! सारी समस्याओं एवं उनके समाधान के बाबूजूद विश्व ( 13 टाइगर रेंज देश ) में बाघों की संख्या को बचाए एवं बनाए रखने के लिए सारी निगाहें भारतीय बाघों की ओर ही हैं क्योंकि आवश्यक अनुवार्तांशक गुणों का भंडारण में बाघों की आवश्यक संख्या भारत के पास है एवं प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में बाघों को बचाने की सबसे बड़ी परियोजना भी भारत के पास है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 सालों की सीख बाघों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी ऐसी आशा से चलो बाघों के लिए जश्न मनाए जो हमारे जीवन का आधार हैं।

# दो दशकों में 134 फीसदी बढ़ी प्राइवेट जेटों की संख्या पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से भी है खतरनाक

भले ही दुनिया भर में अमीर तबके के लिए प्राइवेट जेट शानों-शौकत औं ऐश्वर्य का प्रतीक समझे जाते हैं। लेकिन साथ ही यह निजी विमान पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से कहाँ ज्यादा खतरनाक हैं। हालांकि इसके बावजूद इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बारे में एक नियोर्पोर्ट के हवाले से पता चला है कि पिछले दो दशकों में प्राइवेट जेटों की संख्या बढ़कर दोगुणी से ज्यादा हो गई है। साथ ही इनसे होने वाला उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 2000 में 9,895 प्राइवेट जेट थे, जिनकी संख्या 2022 में 134 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 23,133 पर पहुंच गई है। वहाँ यदि 2022 से जहाँ



१५ अप्रैल 2022 से जुड़े मासिक डॉक्टरों को देखें तो अकेले इसी वर्ष में 3 लाख से ज्यादा निजी उड़ाने भर्ती हुईं। जो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से खतरनाक है। यह जानकारी स्ट्रिट्यूट फॉर पालिसी स्टडीज द्वारा तारीख नई रिपोर्ट हाई फ्लायर्स 2023 में समाप्त होने आई है। यह प्राइवेट जेट और व्यावरण पर कितना दबाव डाल रहे हैं तो सकता है कि यह निजी जहाजों की गणित्यिक विमानों की तुलना में प्रतिवर्ष गती कम से कम 10 गुणा ज्यादा प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। देखा जाए तो उनिया के करीब एक फीसदी लोग विमानों से होने वाले उत्सर्जन के करीब नहीं हिस्से के लिए जिम्मेवार हैं। वहां हामारी की शुरुआत के बाद से गणना करें तो निजी जेटों का उपयोग में करीब 10 फीसदी और इन निजी जहाजों से होने वाले उत्सर्जन में 23 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। जेट पर्यट तौर पर दर्शाता है कि कोरोना वेल्हिंग से इन निजी जहाजों से होने वाले उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई है। वहां रिपोर्ट के कहाना है कि इस साल निजी जेटों की बिक्री अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। रिपोर्ट में दुनिया के कुछ साधन संपत्ति लोगों का जिक्र किया

त अमेरिकी के कुल कार्बन प्रेंट से भी 132 गुणा ज्यादा है। ललब है कि एक औसत अमेरिकी वार्षिक कार्बन फुटप्रिंट करीब 16 टन है। मतलब कि एक साल के दौरान औसत अमेरिकी अमेरिकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 16 टन ग्रीनहाउस का उत्सर्जन करता है। वहीं यदि औसत भारतीय की बात करें तो आँकड़ा करीब 1.9 टन ही है। इसकी इस बात से इंकार नहीं किया जाता कि भारत में भी कई नामी-मीमी हस्तियों के पास अपने खुद के सट जेट हैं।

## सबकी नहीं है पर्यावरण बचाने की जिम्मेवारी

इतना ही नहीं यह भी बता चला है कि नेजी जेट की बिक्री में भी तेजी से का हो रहा है। जहां 2021 में इससे बाजार करीब 2.64 लाख करोड़ (3,230 करोड़ डॉलर) का था, 2022 में बढ़कर 2.78 लाख करोड़ (3,410 करोड़ डॉलर) पर पहुंच था। इसी तरह अनुमान है कि यह 2023 में भी जारी रह सकती है। इसी है कि हवाई जहाजों ने दुनिया बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन म्युनिसिपल एयरपोर्ट्स को आम जनता के पैसे से फण्ड दिया जाता है, लेकिन यह हवाई अड्डे निजी और कॉर्पोरेट जेटों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या इन प्राइवेट विमानों से अलग से टैक्स नहीं लगाए जाने चाहिए। ऊपर से कुछ गिने चुने लोगों द्वारा किया जा रहे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान के लिए उनकी जबाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में जब पूरे विमानन उद्योग को पर्यावरण अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने पर बल दिया जा रहा है, तो क्या इन प्राइवेट विमानों को इसके दायरे में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ गिने चुने लोगों की करनी का फल सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी उस वर्ग की नहीं है जो इसके हो रहे विनाश के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। यह ऐसा वक्त है जब हम सभी को साथ आना होगा, क्योंकि यह धरती सबकी साझा विरासत है, जिसे सबको मिलकर बचाना होगा। हमें समझना होगा कि सिर्फ टैक्स के नाम पर चंद रुपए भर देने से ही हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती।

**सावधान ! जुलाई में लौटेगा अल नीनो, भारत सहित  
दुनिया के कई हिस्सों को कर सकता है प्रभावित**

सावधान! जुलाई म लाटगा अल नाना,  
भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों को  
कर सकता है प्रभावित

वया भारत में मानसून का कर सकता है प्रभावित

प्राद्यानिकों का स्वत्तन, बाम्ब से जुड़े जलवायु वैज्ञानिक रघु मुरुंगुडु ने बताया है कि गर्म होते महासागरों के चलते चक्रवात भी आ सकते हैं, लेकिन अल नीनो इसकी संभावना को कम कर सकता है। उन्होंने बताया कि, वसंत के दौरान गर्म अरब सागर एक मजबूत मानसून का कारण बन सकता है जो अल नीनो के खिलाफ थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति कर सकता है। ऐसे में डब्ल्यूएमओ ने चेतावनी दी है कि दुनिया को अल नीनो के लिए तैयार रहना चाहिए जो अपने साथ दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सूखा लेकर आएगा। इससे बारिश भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही मौसम और जलवायु से जुड़ी चरम घटनाओं में भी चिंगारी लगा सकता है। ऐसे में डब्ल्यूएमओ ने सभी के लिए अलीं वार्निंग पर भी जोर दिया है। डब्ल्यूएमओ के मुताबिक जहां एल नीनो की यह घटनाएं आमतौर पर दक्षिण अमेरिका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाली बारिश में इजाफा कर सकता है। वहाँ दूसरी तरफ इसके विपरीत इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ सकता है।

**क्या होती हैं अल नीनो और ला नीना  
की घटनाएं**

थी कि उभरते अल नीनो के साथ भारत में लू का प्रकोप बढ़ सकता है। देखा जाए तो यह चेतावनी का विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अपडेट से मेल खाती है, जिसमें डब्ल्यूएमओ ने वैश्विक तापमान में वृद्धि की आशंका जर्तई है। गौरतलब है कि इस साल लू का प्रकोप पिछले साल की तुलना में जल्द शुरू हो गया था। इसका असर मार्च-अप्रैल में ही नजर आने लगा था। हालांकि उसके बाद देश के कई हिस्सों में बढ़े पैमाने पर आंधी, बारिश और ओले पिरने की घटनाएं हुईं, जिससे दिन के तापमान में काफी गिरावट आ गई है। इसकी वजह से कई क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत में मार्च सामान्य से अधिक ठंडा हो गया था। देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षेप की एक श्रृंखला के कारण हुआ था। हालांकि आशंका है कि अल नीनो के चलते लू का प्रकोप बढ़ सकता है, जैसा कि 2015 और 2016 में हुआ था। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मुत्युजय महापात्रा ने पिछले हफ्ते भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रभावों को लेकर कहा था कि देश में मानसून पर इसका कोई भी असर मानसून के आधा बीत जाने के बाद ही दिखाई देगा। उनके मुताबिक यह जरूरी नहीं कि हमेशा अल नीनो खराब मानसून की ओर ले जाएगा। बता दें कि 1951 से 2022 के बीच 15 साल अल नीनो का असर दर्ज किया गया था, जिनमें से छह सालों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। वहीं मैरीलैंड विश्वविद्यालय और भारतीय

**भारतीय वैज्ञानिक**  
यह तकनीक चिकित्सा  
उपकरणों की एक नई पीढ़ी  
के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी,  
जिन्हें आने वाले दिनों में  
सर्जन नसों और कई अन्य  
उत्तकों का उपचार करने के  
लिए सर्जरी के दौरान  
आवश्यक हो सकेंगे।

ऑटोग्राफ्ट तकनीक सबसे अच्छी मानी जाती है। नैदानिक उपयोग के लिए विकल्प के रूप में दोबारा अवशोषित करने योग्य (बायोरसोर्बेल) पॉलिमर आधारित नलिका का पता लगाया जा रहा है। लेकिन यह उपचार नीतियां भी कई तरह की बाधाओं से ग्रस्त हैं जैसे कि ऑटोग्राफ्ट के मामले में डोनरसाइट बीमारियां और टांके की आवश्यकता जिसमें अत्यधिक कुशल माइक्रोसर्जरी की जरूरत पड़ती है और इसमें टांके से उत्पन्न होने वाली अन्य जटिलताएं भी आपसिंह हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो सर्जरी की जटिलता को कम करके नसों का तेजी से उपचार में मदद कर सकती है। यह त्रि-आयामी (थ्री डी) प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग से बनाई गई नई मार्ट जेल-आधारित शीट है। इसका उपयोग नर्जरी के दौरान नसों या तंत्रिका नलिका बनाने के लिए किया जा सकता है जो ट्यूब और स्वर्यं-घूम सकती है सबसे बाहरी या अरिधीय नसों के उपचार के लिए अभी भी शामिल ह।

उपचार के इन कमियों को दूर करने के लिए बैंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के शोधकर्ताओं ने त्रिआयामी (थ्री डी प्रिंटिंग) तकनीक का उपयोग करके एक स्मार्ट जेल आधारित शीट डिजाइन की। यह तंत्रिका नलिका बनाने के लिए सर्जरी के दौरान एक ट्यूब के रूप में स्वयं उसमें घूम सकती है। थ्री डी प्रिंटिंग में उस भाग का एक आभासी मॉडल के मदद से सामग्री के परत दर परत जमाव द्वारा, डिजाइन-सॉफ्टवेयर का उपयोग करके



बनाया जाता है। निर्माण के बाद श्री डॉ मुद्रित भाग स्वयं आकार में बदलाव ल सकता है। ऐसी तकनीक को अब व्यापक रूप से चार आयामी (फोर डी प्रिंटिंग) के रूप में जाना जाता है। हाल ही के एक

अध्ययन में प्रोफेसर कौशिक चटर्जी के नेतृत्व में आईआईएससी की टीम ने जेल से पूर्व निर्धारित पैटर्न में श्री डी प्रिंटिंग द्वारा एक दो सतहों वाली जैल शीट तैयार की। जेल के फॉर्म्यूले को पानी से अलग तरह से प्रतिक्रिया

करने के लिए चुना गया था। जब सूखे जेल शीट को पानी में डुबाया गया तो यह तेजी से फूल गया और एक नलिका के रूप में बदल गया। जेल के इस व्यवहार और मन चाहे आकार के ट्यूब उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका अनुमान कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग द्वारा लगाया जा सकता है।

से तंत्रिका के सिरे को बढ़ाया जा सकता है। जब फोर डी मुद्रित तंत्रिका नली का उपयोग किया गया तो चूहों में 45 दिन तक मापे गए तंत्रिका फिर से उत्पन्न होने में भारी सुधार देखा गया। यह शोध एडवांस्ड हेल्थकेयर मटेरियल्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं के इस काम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैधानिक निकाय द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय असांस्ट द्वारा

इसके बाद जल शाट का बहुत पतला नैनोमीटर स्केल के तंत्रिका तंतुओं से लपेटा जाता है ताकि शरीर की कोशिकाओं को जेल शीट पर चिपकने में सक्षम बनाया जा सके। आईआईएससी की टीम ने रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर चूहों की साइटिका की नस में दो मिलीमीटर के गहरे भाग का उपचार और फिर से उत्पन्न करने के लिए फोरडी नली का परीक्षण किया। इसके लिए तंत्रिका में जहां समस्या थी उसके नीचे शेष मोरफिंगशीट को रखा गया और समस्या-ग्रस्त तंत्रिका के चारों ओर एक नली बनाने के लिए शीट को प्रेरित किया गया। प्रत्यारोपित नलिका की सहायता

## यूक्रेन विवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्रित रहेगी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक

■ नई दिल्ली

**समूह से जुड़े अन्य जल्दी मामलों के साथ जुलाई महीने में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन का बैठक होगा।**

**सम्मेलन के मुद्दे पर भी मंथन करेंगे समूह देशों के विदेश मंत्री।**

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों के द्वारा सम्मेलन की युवराज से गोवा में शुरूआत हो गई है। इसी तहत शुक्रवार 5 मई को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें समूह से जुड़े तमाम जरूरी मामलों के अलावा यूक्रेन विवाद और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर विस्तृत आधार पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में जुलाई-2023 में नई दिल्ली में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन का एजडा भी तय किया जाएगा। जिसकी अधिकतम प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी करेंगे। उनके अलावा इसमें चीन के विदेश पर्षद शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और समूह के अन्य भागीदार देशों के प्रमुख भी शिखर करेंगे। सूची ने यूरुवार के बताया जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मौटे तौर पर 15 नियम लिए जा सकते हैं। इन पर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से जुड़े अन्य जल्दी मामलों के साथ जुलाई महीने में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन का बैठक होगा।

निर्णयों में विदेश व्यापार से लेकर सुरक्षा और समूह से जुड़े हुए समाजिक, सांस्कृतिक मामलों में एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ावे पर चर्चा की जाएगी। बताते चलें कि एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में की गई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने हैं।

**बैठक से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे**

उधर शुक्रवार को गोवा में होने वाली समूह के विदेश

मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन में जारी मौजूदा विवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एससीओ की

बैठक में चर्चा किए जाने की किसी तरह की कोई

समूह के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श करने का

अवसर प्रदान करती है। समूह में सुधार और आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय और वैश्वक मूद्दों पर पर्चाचे के अलावा एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकारना भी विचारिया में है। जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन में कुवैत, यामान, मालदीव और यूर्एई के संवाद भागीदार यानी डायलॉग पार्सन के रूप में मौजूद दिए जाने को लेकर भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा किए जाने की किसी तरह की कोई सम्भावना नहीं है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

सचिव (आर्थिक संबंध) दामू रवि ने बताया कि

विदेश मंत्रियों की बैठक के पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण

कार्य उन नियमों की स्थिति की विश्लेषण करना है।

जिनमें एससीओ शिखर सम्मेलन में मौजूद प्रदान की

जाएगी। यह बैठक एससीओ के अंदर बहुआयामी

सहयोग के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श करने का

अवसर प्रदान करती है। समूह में सुधार और आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय और वैश्वक मूद्दों पर पर्चाचे के अलावा एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकारना भी विचारिया में है। जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन में कुवैत, यामान,

मालदीव और यूर्एई के संवाद भागीदार यानी

डायलॉग पार्सन के रूप में मौजूद दिए जाने को लेकर

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे

भी अतिम नियम लिया जा सकता है। बैठक से चर्चा की जाएगी। उक्त

समूह से दूर होने वाले भारत-पाक के मुद्दे









